domestic support given to agriculture by member countries of GATT. It does not take into account a large variety of support measures for the agricultural sector. The AMS comprises of two components viz. product specific and non-product specific support. For the purpose of calculating the domestic support to agricultual producers, both product specific AMS and non-product specific AMS are taken product account. During the base period (1986-88) the average product specific AMS was about Rs. minus 24442.2 crores and the non-product specific AMS was estimated at Rs. 4581.4 crores. The total AMS was, therefore, minus 19,860 crores. India has not taken any reduction commitments for the AMS.

Revival of Students Information Bureau

672. SHRI RAM NATH KOVIND: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether some "Students Informaion Bureau" used to function above the Central Secretariat Library in the past;

(b) whether the Bureau used to provide very useful information to students of different academic qualifications to choose their career;

(c) whether the Bureau ahs since been closed down, causing severe strain and incovenience to students and making them victims of touts and anti-social institutions to pay huge amount for the said information;

(d) whether the Government propose to revive the said Bureau in the near future; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPTT. OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) to (e) Yes, Sir. The work of 'Students Information Service Unit' (SIS) of the Department of Education was transferred to the Association of Indian Universities (AIU) with effect from 1st July, 1987 to avoid duplication and save manpower. It continues to function effectively and responds to enquiries from students, parents and others in India and abroad on availability/duration/ eligibility requirements of different courses in Indian Universities/other institutions in the country.

The unit has compiled comprehensive information on educational programmes conducted by Universities, Polytechnics, Industrial Training Institutes, Government Departments, Research Laboratories, etc. AIU share the information with all Government Departments, including the Ministry of External Affairs/Ministry of Human Resource Development/Indian Council for Cultural Relation who are concerned with nomination of foreign students and all others. Besides, AIU: (i) produces extensive literature on recognised university courses/education through the Handbooks: (ii) releases new items through the Employment News on institutions operating as self-styled universities in the country.

शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त किया जाना

673. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है,

(ख) सरकार तथा सरकार की अधीनस्थ सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं/अभिकरणों द्वारा देश में साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं, और

(ग) देश में साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में अब तक हुई राज्य-वार प्रगति का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को वर्ष 2005 तक 15-35 वर्ष की आयु-वर्ग के व्यक्तियों को साक्षर बनाने का दायित्व सौंपा गया है। साक्षरता के लिए प्रमुख दृष्टिकोण स्वयंसेवक-आधारित संपूर्ण साक्षरता अभियानों के माधयम से हैं जो जिलों द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं के आधार पर शुरू किया गया है संपूर्ण साक्षरता अभियान जिला साक्षरता समितियों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं जिनमें स्वैच्छिक एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। जिन क्षेत्रों में संपूर्ण साक्षरता अभियान अभी तक शुरू नहीं किए हैं उन क्षेत्रों में स्वैच्छिक एजेंसियों को छोटे-छोटे क्षेत्रों में साक्षरता संबंधी कार्य शुरू करने कि लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरूआत से 31-3-96 तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की शुरूआत से 31-3-96 तक साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	साक्षर बनाए गए व्यक्ति
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	7311694
2.	अरूणाचल प्रदेश	59612
3.	असम	937861
4.	बिहार	4173802
5.	गोवा	71237
6.	गुजरात	5601239
7.	हरियाणा	250134
8.	हिमाचल प्रदेश	471251
9.	जम्मू और कश्मीर	163892
10.	कर्नाटक	3626834
11.	केरल	1560152
12.	मध्य प्रदेश	3499753
13.	महाराष्ट्र	4407924
14.	मणिपुर	67371
15.	मेघालय	84225
16.	मिजोरम	61919
17.	नागालैंड	63123
18.	उड़ीसा	1751892
19.	पंजाब	527508
20.	राजस्थान	2390703
21.	सिक्किम	13604
22.	तमिलनाडु	5482958
23.	त्रिपुरा	81387
24.	उत्तर प्रदेश	5276569
25.	पश्चिम बंगाल	7729489
26.	अंडमान और निकाबार दीव समूह	14492
27.	चंडीगढ़	40404
28.	दादरा और नगर हवेली	7293
29.	दमन और दीव	3451
30.	दिल्ली	344518
31.	लक्षदीप	986
32.	पांडिचेरी	99965
	कुल	56108067

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन का निर्माण

674. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन की आधारशिला कब रखी गई थी; और

(ख) इस रेल लाइन को बिछाने के कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) प्रस्तावित लाइन के लिए अब तक कोई आधारशिला नहीं रखी गयी है।

(ख) ललितपुर से सिंगरौली तक एक नई लाइन को सर्वेक्षण किया गया है। फील्ड वर्क पूरा हो चुका है तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट 31.8.96 तक प्राप्त हो जाने की संभावना है।

सर्वेक्षण के परिणाम आ जाने पर परियोजना पर आगे विचार करना संभव हो सकेगा।

Purchase of wagons

675. SHRI DIPANKAR MUKERHJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of wagons ordered in terms of FWUs in 1995-96;

(b) the break-up of orders placed on PSUs and private companies;

(c) the number of wagons purchased through Wagon India and through open tender;

(d) the number of wagons to be procured in 1996-97; and

(e) the number of wagons ordered so far with break-up of wagon orders placed through Wagon India and through open tendering.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) During 95-96 orders for 17685 four wheeler units (FWUs) were placed.

(b) Out of these, 1600 FWUs were ordered on Railway workshops and out of remaining 16085 FWUs, 10627.5 FWUs were ordered on Public Sector units and 5457.5 FWUs on Private Companies.